

as per the Schedule drawn up for the purpose.

#### Rationalisation of court fees

2819. SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state whether the Government are considering to compensate the States for the revenue losses in case of rationalisation of court fees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): (a) No, Sir.

#### Collaboration with Japan in connection with expansion and maintenance of telecommunication projects

2820. SHRI HARISH RAWAT: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the details of the agreement made by the Government with the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan in connection with the expansion and maintenance of the telecommunication projects in the country; and

(b) what is the amount of loan received and what are the conditions of its repayment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). Since 1977 the Government of India have been proposing from time to time to the Government of Japan for foreign exchange assistance to the Telecommunication Sector. The Government of Japan through the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan have given five loans aggregating a total of 32.1 billion yen for procurement of various types of equipments.

These loans are to be repaid in a period of 30 years with an initial period of grace of 10 years. The first loan of 1977 carried a rate of interest of 3.5 per cent and the remaining four loans carry 2.75 per cent rate of interest per annum.

#### धौली गंगा बाँध में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना

2821. श्री हरीश रावत: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौली गंगा, गौरी गंगा और शारदा घाटी में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करने हेतु एन. एच. पी. सी. और उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रारम्भ में कितनी परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जायेगा और सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या एन. एच. पी. सी. द्वारा इन नदियों के अत्यधिक पन बिजली उत्पादन क्षमता के मूल्यांकन का भी सर्वेक्षण किया जाएगा?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारम्भिक अध्ययनों के आधार पर शारदा घाटी में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया है। प्रस्तावित स्कीमों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 3340 मेगावाट बताई गई है। शारदा घाटी में धौलीगंगा (300 मेगावाट) तथा टनकपुर (120 मेगावाट) के अन्वेषण सम्बन्धी कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में किए जा रहे हैं। धौलीगंगा के अन्वेषण सम्बन्धी कार्य 1984 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम है। आधुनिक प्रांशॉगिकी का प्रयोग करके अन्वेषण सम्बन्धी कार्य की अवाध को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टनकपुर परियोजना के निर्माण पूर्व अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सितम्बर, 1982 तक पूरे हो जाने की आशा है। शारदा घाटी में अन्य जल विद्युत परियोजनाओं नामशः गौरी गंगा तथा पूर्वी राम गंगा आदि के अन्वेषण कार्य तथा परवर्ती क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत तथा लाभों के बटवारे के फार्मूला मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उसकी स्वीकृति के लिये उठाया गया है।